

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II  
(अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

**द हिन्दू**

2 जुलाई, 2019

### “जी-20 शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है।”

एक मंच के रूप में, G-20 को अक्सर बैठकों से प्राप्त हुए परिणामों के बजाय इसके आयोजन में होने वाली द्विपक्षीय वार्ताओं को अधिक बारीकी से देखा जाता है। G-20 (19 राष्ट्र और यूरोपीय संघ) देश, जो दुनिया के नॉमिनल जीडीपी के 85% हिस्से को कवर करते हैं, उन्होंने अन्य सदस्यों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तरों पर अपने ऐच्छिक मुद्दों को उठाया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 द्विपक्षीय बैठकें करते हुए ओसाका में G-20 शिखर सम्मेलन के अवसर का पूरा इस्तेमाल किया है, जिनमें नौ द्विपक्षीय, आठ अलग से बैठकें और रूस-भारत-चीन, जापान-अमेरिका-भारत और ब्राजील-रूस-भारत-चीन-दक्षिण अफ्रीका समूह से बातचीत शामिल हैं।

व्यापार तनाव में वृद्धि को देखते हुए सबसे अधिक प्रत्याशित बैठक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग और श्री मोदी के साथ थी। दोनों ने एक सौहार्दपूर्ण तरीके से बैठक को समाप्त किया, लेकिन कोई सफलता या ‘बड़े सौदे’ के मुद्दे पर सहमत नहीं हो सके।

भारतीय और अमेरिकी वाणिज्य मंत्री फिर से व्यापार के मुद्दों पर गतिरोध को हल करने की कोशिश करने के लिए मिलेंगे और अमेरिका एवं चीन ने दरों को बढ़ाने के अपने रुख को रोकने का फैसला लिया है। राष्ट्रीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर तनावों के प्रभाव को देखते हुए दोनों तथ्य भारत के लिए एक राहत के रूप में हैं।

श्री मोदी ने G-20 विचार-विमर्श में कई भारतीय चिंताओं को उठाया है, जिसमें भागें आर्थिक अपराधियों और जलवायु परिवर्तन के वित्तपोषण पर सहयोग की आवश्यकता शामिल हैं। भारत ने जापानी प्रधानमंत्री शिंजो अबे द्वारा बढ़ावा दिए जा रहे डिजिटल अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन में भाग लेने से इन्कार करके एक सख्त संदेश भेजा है।

भारत ने इन्कार इसलिए किया क्योंकि G-20 घोषणा में शामिल ‘विश्वास के साथ डाटा का मुक्त प्रवाह’ की शिंजो अबे की योजना भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रस्तावित डेटा स्थानीयकरण के दिशा निर्देश से अलग है। समुद्र प्रदूषण प्रबंधन, लैंगिक समानता और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए ठोस प्रयासों जैसे मुद्दों पर, G-20 ने अपनी- अपनी सर्वसम्मति प्रदान की।

गौरतलब हो कि 2020 में सऊदी अरब, 2021 में इटली और 2022 में भारत G-20 की मेजबानी करेंगे। कई वैश्विक चुनौतियाँ, जैसे जलवायु परिवर्तन और इसका प्रभाव, 5G नेटवर्क के साथ गति और राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतों के बीच संतुलन, साथ ही साथ प्रौद्योगिकी-संचालित आतंकवाद, समूहन के लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा तथा सरकार को इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

भारत को अपने सिस्टम में मौजूद कुछ असमानताओं से निपटने के लिए G-20 को अधिक प्रभावी बनाने की कवायद का नेतृत्व करना चाहिए। G-20 एक महत्वपूर्ण मंच है जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है और इसे एक या दो सदस्यों के प्रभाव में आकर समय-समय पर स्थायी विकास और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के अपने मूल उद्देश्य से नहीं हटना चाहिए।

## जी-20

### क्या है?

- सितंबर, 1999 में जी-7 देशों के वित्त मंत्रियों ने जी-20 का गठन एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के तौर पर किया था। यह मंच अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के साथ ब्रेटन बुड़स संस्थागत प्रणाली की रूपरेखा के भीतर आने वाले व्यवस्थित महत्वपूर्ण देशों के बीच अनौपचारिक बातचीत एवं सहयोग को बढ़ावा देता है।
- यह समूह (जी-20) अपने सदस्यों के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और कुछ मुद्दों पर निर्णय करने के लिए प्रमुख मंच है। इसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। जी-20 के नेता वर्ष में एक बार साथ मिलते हैं और बैठक करते हैं।
- इसके अलावा, वर्ष के दौरान, देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर वैश्वक अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार लाने, वित्तीय नियमन में सुधार लाने और प्रत्येक सदस्य देश में जरूरी प्रमुख आर्थिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए नियमित रूप से बैठक करते रहते हैं।
- इन बैठकों के अलावा वरिष्ठ अधिकारियों और विशेष मुद्दों के नीतिगत समन्वय पर काम करने वाले कार्य समूहों के बीच वर्ष भर चलने वाली बैठकें भी होती हैं।
- ये देश विश्व के आर्थिक उत्पादन के 85 फीसदी का और जनसंख्या के 60 फीसदी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विश्व बैंक और आईएमएफ के प्रमुख भी इस संगठन के सदस्य हैं। जी-20 की पहली बैठक दिसंबर, 1999 में बर्लिन में हुई थी।

### स्थापना और शुरुआत

- जी-20 की शुरुआत, 1999 में एशिया में आए वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की बैठक के

तौर पर हुई थी। वर्ष 2008 में जी-20 के नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था और समूह ने वैश्वक वित्तीय संकट का जवाब देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

- इसकी निर्णायक और समन्वित कार्यवाई ने उपभोक्ता और व्यापार में भरोसा रखने वालों को शक्ति दी तथा आर्थिक सुधार के पहले चरण का समर्थन किया। वर्ष 2008 के बाद से जी-20 के नेता आठ बार बैठक कर चुके हैं।
- जी-20- वित्तीय स्थिरता बोर्ड, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन के साथ मिलकर काम करता है। कई अन्य संगठनों को भी जी-20 की प्रमुख बैठकों में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

### जी-20 के सदस्य देश

- जी-20 के सदस्य वैश्वक सकल घरेलू उत्पाद का करीब 85 फीसदी, वैश्वक व्यापार के 75 फीसदी और विश्व की आबादी के दो-तिहाई से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं।

### सदस्य देशों के नाम

- अर्जेटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ

### क्यों पड़ी जी-20 जैसे मंच की जरूरत?

- जी-20 का गठन उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के साथ विचार-विमर्श एवं समन्वय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था।
- विश्व के सात प्रमुख औद्योगिक देश कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे पहले जी-20 में शामिल हुए।

## Expected Questions (Mains Exams)

प्रश्न: हाल ही में संपन्न जी-20 शिखर सम्मेलन में भारत की भूमिका को बताते हुए यह भी चर्चा कीजिए कि इस सम्मेलन में कौन-कौन से मुख्य मुद्दे वैश्विक समस्याओं के लिहाज से महत्वपूर्ण रहे हैं? ( 250 शब्द )

**Q.** Explaining the role of India in G-20 summit, discuss what global problems were important in this summit. (250 Words)

**नोट :** 1 जुलाई को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c) होगा।